



अधिकतम : 24° C  
न्यूनतम : 13° C

अबरे छुपाता नही, छापता है

# शाह टाइम्स

हल्द्वानी, मंगलवार 24 मार्च 2026 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 206 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00



विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें।  
मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com

चैन कृपा पक्ष 6 विक्रमी सप्ताह 2083

4 शबाल 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुगदाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



बंगाल में भी दिखाई देगा पीडीए का असर: अखिलेश यादव



युद्ध के बीच गैस-तेल से ईरान की हो रही रिकॉर्ड कमाई



पश्चिम बंगाल चुनाव: सत्ता की जंग से बड़ी चुनाव आयोग की साख की अग्नि परीक्षा



ईरान ने अमेरिका का एफ-15 लड़ाकू विमान मार गिराया

## संक्षिप्त समाचार

**NIA ने लालकिला विस्फोट जांच में कश्मीर में कई जगहों पर मारे छापे**  
श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में लालकिले के पास पिछले साल 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट मामले की जांच के तहत कश्मीर में कई जगहों पर छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ये छापे श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में छह जगहों पर उन लोगों से जुड़े ठिकानों पर मारे गए, जिन्हें धमाके के पीछे के आतंकी मांड्यूल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने बारामूला जिले के रफीकाना के रहने वाले डा. बिलाल नसीर मल्ला के घर पर तलाशी ली, जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। कुपवाड़ा जिले के लंगते इलाके में भी एक और तलाशी ली गई।

## विकसित भारत के लिए आय बढ़ानी होगी: विपक्ष

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष ने सोमवार को कहा कि सरकार विकसित भारत की सिर्फ बात करती है और इसके लिए उसके पास कोई ठोस नीति नजर नहीं आती। लोकसभा में 'वित्त विधेयक 2026' पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के डा. अमर सिंह ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति आय करीब 3000 डॉलर है, जबकि विकसित भारत के लिए यह आमदनी 14000 डॉलर प्रति व्यक्ति होनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार जो दावा करती है और जो बुनियादी स्थिति है उसमें बहुत बड़ा फर्क है और इस गैप को बंद करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने हुए सरकार नजर नहीं आती है।

## अमृतसर में नशा तस्करी मांड्यूल का भंडाफोड़, 2 पकड़े

अमृतसर। पंजाब में अमृतसर काउंटर इंटेल्जेंस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशा तस्करी के एक मांड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से पांच किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोमवार को बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस मांड्यूल के तार पाकिस्तान स्थित तस्करी से जुड़े हुए हैं।

## उत्तर प्रदेश में गेहूं का एमएसपी ₹2585 हुआ

शाह टाइम्स ब्यूरो



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि दो प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बैठक में किसानों, ऊर्जा, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विचार-विमर्श, जिन्हें राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट को बैठक के बाद मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फैंसलों की जानकारी दी। श्री शाही ने कहा कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585

रुपये प्रति कुंतल तय किया है। प्रदेश में गेहूं की खरीद 30 मार्च से 15 जून तक की जाएगी और इसके लिए 6500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को उतारई, सफाई आदि के लिए 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान भी दिया जाएगा। इस बार 30 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 50 लाख टन तक खरीद का अनुमान है। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि

ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। घाटमपुर में 660 मेगावॉट की तीन यूनिट परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड स्थित कोल ब्लॉक के विकास के लिए 2242.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना से 270 मिलियन टन कोयला उत्पादन का अनुमान है और बिजली दरों में करीब 80 पैसे प्रति यूनिट तक कमी आने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में भी पहल की गई है। चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 80 एकड़ क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 'नवयुग नगर पालिका योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के 58 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 55 नगर पालिका परिषद और 3 नगर पंचायत शामिल हैं। श्री शर्मा ने बताया कि 145 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्षों में लागू होने वाली इस योजना में 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले 24 निकायों को प्राथमिकता दी जाएगी।

# युद्ध का असर लंबा चल सकता है, हमें कोरोना संकट की तरह तैयार रहना होगा: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत का रुख किया स्पष्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बताया कि मिडिल ईस्ट में हालत चिंताजनक है। देश के सामने चुनौतियां बढ़द जा रही हैं। दुनियाभर के लोग युद्ध रोकने के लिए आग्रह कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और इस जंग पर भारत का क्या रुख है, वो स्पष्ट किया। पीएम मोदी ने बताया कि बीते दिनों होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। संकट के इस समय में देश को एक और तैयारी भी है, जो बहुत काम आ रही है। पिछले 11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ एक से डेढ़ प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपैसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब साढ़े 4 करोड़ बैरल कम ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। हालांकि, पीएम मोदी ने बताया कि ईरान-इजरायल जंग का असर लंबा चल सकता है। हमें कोरोना संकट की तरह तैयार रहना होगा।

## संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी ने व्यापक चर्चा की रखी मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर जो बयान दिया है उसमें कोई नई बात सामने नहीं आई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री ने लोकसभा में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देशवापसी से लेकर एलपीजी जैसी जरूरी व्यवस्थाओं पर सरकार के कदमों की जानकारी दी।

मोदी ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। ईरान से अब तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित लौट चुके हैं, जिनमें से 700 से अधिक मेडिकल छात्र हैं।

ईरान और अमेरिका- इजरायल युद्ध का सोमवार को 24वां दिन था। ये जंग कब रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस जंग ने दुनियाभर के सामने ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत में भी गैस की किल्लत महसूस की जा रही

है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भारत की मौजूदा विदेश नीति और केंद्र सरकार पर कई सवाल उठा रही हैं। इन्हीं सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को लोकसभा में दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र

## सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामले में दोबारा सुनवाई के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

शाह टाइम्स ब्यूरो



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक तलाक के मामले को नए सिरे से सुनवाई करने को कहा गया था। यह मामला इसलिए चर्चा में आया, क्योंकि एक परिवार न्यायालय ने तलाक की मंजूरी देते समय कानून की ऐसी धारा का इस्तेमाल कर दिया था, जो असल में है ही नहीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसने पुराने तलाक को रद्द कर नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया था। फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने दोबारा सुनवाई पर रोक लगा दी है। पूरा मामला तब उलझ गया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाया कि परिवार न्यायालय के न्यायाधीश ने अलग-अलग कानूनों को आपस में मिला दिया था। कंस हिंदू

## ट्रम्प बोले जंग खत्म करने को हमारी बात हुई, ईरान का इन्कार

शाह टाइम्स ब्यूरो



वाशिंगटन/ तेहरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह समाधान के मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी तरह के हमलों को पांच दिन के लिए टालेंगे, लेकिन ईरान को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत वाले बयान को नकार दिया है। इससे पहले ट्रंप सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो दिनों में मध्य पूर्व में टकराव के पूरी तरह समाधान को लेकर बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है। इस रचनात्मक बातचीत के रुख और माहौल को देखते हुए, जो पूरे सप्ताह जारी रहेगी, मैंने वॉर डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को पांच दिन के लिए टाल दिया

जाए। यह फैसला बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई उस बात को नकारते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है।

अमेरिका को आईआरजीसी की कड़ी चेतावनी, 'हर हमले का मिलेगा जवाब' तेहरान। इस्लामिक रिवालयुशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी खतरे का बराबर और प्रतिरोधक जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी ने सोमवार को जारी बयान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों का जवाब दिया, जिनमें कहा गया था कि ईरानी बल क्षेत्रीय जल विलवणीकरण संयंत्रों को निशाना बना सकते हैं। आईआरजीसी ने आरोप लगाया कि युद्ध की शुरुआत अमेरिकी सेना ने की और अब तक बच्चों सहित कई नागरिकों को निशाना बनाया है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी हलों में जल अवसंरचना को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें केशम द्वीप का विलवणीकरण संयंत्र शामिल है।

**PATANJALI wellness**  
Yoga, Ayurveda & Naturopathy

**पतंजलि वेलनेस में सेवा (जॉब) का अनुपम अवसर**

पतंजलि वेलनेस कर्मयोगी बनकर सेवा के द्वारा विश्व के सबसे बड़े योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के आंदोलन से जुड़ें। विश्व के सबसे बड़े योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के सेवा अभियान के लिए पतंजलि वेलनेस में योग्य एवं अनुभवी थैरेपिस्ट / योगाचार्य / वैद्य गण (प्रस्नाथक को प्राथमिकता) के लिए कर्मयोगियों की आवश्यकता है।

**थैरेपिस्ट हेतु अर्हता (Eligibility):** न्यूनतम 10वीं पास / पंचकर्म डिप्लोमा / नेचरोपैथी डिप्लोमा / कार्य से सम्बंधित अनुभव + उत्तराखंड आयुष चिकित्सा कौंसिल द्वारा पंजीकृत।  
**आयु:** 18 से 35 वर्ष  
**प्रशिक्षण अवधि:** 2 माह  
**अन्य सुविधाएँ:** भोजन, आवास व बस

**योगाचार्य हेतु अर्हता (Eligibility):** योग स्नातक / स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग / कार्य से सम्बंधित अनुभव।  
**आयु:** 18 से 35 वर्ष

**वैद्य हेतु अर्हता (Eligibility):** BAMS/BNYS/MD (आयुर्वेद/नेचुरोपैथी) / Ph.D. (आयुर्वेद/नेचुरोपैथी) / कार्य से सम्बंधित अनुभव + उत्तराखंड आयुष चिकित्सा कौंसिल द्वारा पंजीकृत।

**वेतन / मानदेय: योग्यता एवं कार्य दक्षता के अनुसार।**

**कार्य स्थल: पतंजलि वेलनेस/ योगग्राम/ निरामयम्, हरिद्वार, उत्तराखंड**

**संपर्क करें: 8954-666-111**  
89548 91711 / 72170 45416 / 82720 68187  
अपना बायोडाटा / CV/ RESUME नीचे दिए गए Whatsapp अथवा ई-मेल पर भेजें  
**895489-6661 | career@patanjaliwellness.com**

**पतंजलि के नाम पर किसी भी प्रकार के (एडमिशन, बुकिंग, नौकरी, फ्रैंचाइजी आदि) ऑफर के बहाने होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें।**

हम नौकरी हेतु किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करते हैं तथा पतंजलि वेलनेस में बुकिंग हेतु केवल अधिकृत नंबर 8954-666-111 पर ही संपर्क करें; ऑनलाइन भुगतान करने से पहले संबंधित बैंक खाते की पुष्टि अवश्य कर लें।



सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर परेड ग्राउंड में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री

चार वर्षों में राज्य कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का बना साक्षी: धामी

शाह टाइम्स ब्यूरो देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को भावना सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित चार साल बेमिसाल कार्यक्रम का दौरा प्रबलित कर शुभारंभ किया। इस वार्षिक परेड ग्राउंड में लगे स्टालों का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने यहां पर सेल रोटी बनाई। सीएम ने कनक चौक से कांक्रिट स्थल तक रोड शो में प्रतिभाग किया, साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रदर्शनों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर परेड ग्राउंड में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रशाखासिंघों को नवरात्र की शुभकामनाएं देने के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि आज से चार वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता ने सभी मिशनों को तौलकर, उन्हें पूरा: खन्न को



सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण के साथ ही विकास प्रदर्शनों का भी किया अवलोकन

सेवा का अवसर प्रदान किया था। इसके बाद इसी मैदान में रापथ ग्रहण के दौरान उन्होंने राज्य ओलंपिककारियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देने के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि आज से चार वर्ष पूर्व प्रदेश की जनता ने सभी मिशनों को तौलकर, उन्हें पूरा: खन्न को

सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में बाबा केदारनाथ को दिव्य धारा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसलिए प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के मुख से निकले इन शिवांमयी शब्दों को चरितार्थ करने

के संकल्प को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने बीते चार वर्षों में जल सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं पंचवटी कनेक्टिविटी को मजबूत कर नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया है। वहीं,

विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास का निम्न प्रस्तुत किया है। इन्होंने प्रयासों से बीते चार वर्षों में राज्य एंटीसी कई ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी बना है जो किसी भी छोटे राज्य के लिए असंभव समझी जाती थीं। सीएम ने कहा कि पहली बार

समारोह में इन्की रही मौजूदगी समारोह में कैबिनेट मंत्री सुधीर उन्धवाल, गणेश शर्मा, खवानत दास, राम सिंह कौडा, राज्य सार संपर नेहा बंसल, मेयर सीध धरलियाल, विभागीय सहदेव पुंडीर, उमेश शर्मा काक, निगमि चमली, सिला कपूर, मुना सिंह चौधरी, कुचरपुन मेहता, मुख्य सचिव आर. वरधन, पुलिस महानिदेशक दीपन सेठ, प्रमुख सचिव डा. आर. मोनाली सुंदर, सचिव एसएन पांडेय और आतुक महबाल विपन्न शांकर पांडेय, जिवांमिपरीतरी देवगुंड सचिव बंसल उपस्थित रही।

राज्य में जी-20 जैसे वैश्विक सम्मेलन को बैठकों का सफल आयोजन किया गया, वहीं राष्ट्रीय खेलों का भी भव्य आयोजन किया गया।

धानी ने नहीं, पहली बार उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है।

30 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि पहले प्रदेश में नकल और पेंपर लोक के कारण प्रतिभावाली युवाओं के सपने चूर-चूर हो जाते थे। इसलिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई। जिसके परिणामस्वरूप पिछले साढ़े 4 बार वर्षों में राज्य के 30 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों को सफलतापूर्वक प्राप्त हुईं। आज 100 से अधिक नकल माफिया जेल की हवा खा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में प्रदेश में पंचधारा के मामलों में केवल छोटी महशुलों पर ही कार्रवाई होती थी। लेकिन आज प्रदेश में बड़े आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है।

कहा- देवभूमि के देवल बचाने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देवभूमि के देवल को रक्षा के लिए उद्योगपति को भी संरक्षित रखने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जहां एक ओर प्रदेश में सख्त धर्मनिरपेक्ष विरोधी और देश विरोधी कानूनों को लागू किया, उन्हींमें कहा कि प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 12 हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया है। साथ ही छह मंत्रि धारण कर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालमिनि संयोजित किया। प्रधानमंत्री ने सख्त नागरिक संहिता कानून लागू कर सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया है, जिसे देश भर में राष्ट्रीय स्तर के लोगों में सराहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी वर्ष से देवल से उतराखंड में सभी मस्तरों में सरकारी बाईड मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा।



कनक चौक से परेड ग्राउंड कार्यक्रम स्थल तक रोड शो निकालते सीएम धामी।



परेड ग्राउंड में लगे स्टाल में सेल रोटी बनाते मुख्यमंत्री धामी।



कार्यक्रम के दौरान बच्चों को उपहार भेंट करते हुए सीएम पुष्कर धामी।



कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड में लोगों का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री धामी।



दिवांग्य व्यक्तियों को सुदृढ़ सहितक भेंट करके के दौरान मुख्यमंत्री धामी।



चार साल बेमिसाल कार्यक्रम में मौजूद अतिथिगण व उन्मत्तक जसमूम।

धामी सरकार के चार साल में केंद्र से मिली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी

चार साल बेमिसाल: 01 सड़क, रेल, रोपवे, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं को मिली गति जल संसाधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम से जमानती और समय बांध परियोजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिन्हें कई सरकार से अंतिम मंजूरी मिल गई है। ये परियोजनाएं न केवल पंचवटी और सिंचाई को जलकों को पूरा करेंगी, बल्कि शाही निस्तर और औद्योगिक विकास के लिए भी आधार तैयार करेंगी। नतीजा चार साल में रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज

सड़क एवं रोपवे प्रोजेक्ट

बीते चार सालों में सड़क और रोपवे परियोजनाओं में भी गति पकड़ी है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस रोड, नजीबाबाद-अफजलपुर बाईपास और सितारगंज-दुकरा मोटरगाड़ी जैसे प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब रोपवे पर भी काम शुरू हो जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्राफिकश में 100 करोड़ रूपी का लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती मिलेगी।

बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ा असर

ये लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं टनकरपुर-बांशहरा रोड, नजीबाबाद-अफजलपुर बाईपास और सितारगंज-दुकरा मोटरगाड़ी जैसे प्रोजेक्ट्स इसका उदाहरण हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब रोपवे पर भी काम शुरू हो जा रहा है। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्राफिकश में 100 करोड़ रूपी का लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। इससे उत्तराखंड को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती मिलेगी।

अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक सूचकांक तक शानदार सुधार

चार साल बेमिसाल: 02 पिछले चार वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण को सुआ है। इसी संस्कार में 'विकसित रहित संकल्प' के साथ प्रदेश को संचालित विकास से लिए कार्य किया है। नतीजा कल्याण, रोजगार सुख, बुनियादी ढांचे के विस्तार और निवेश को बढ़ावा देने हमारी अभियंता रही है। आज उत्तराखंड तेजी से देश के अग्रणी स्थानों में शामिल हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री 889 करोड़ रूपे दर्ज की गई, इस तरह वर्ष 2021-22 के मुकाबले जीएसडीपी में डेढ़ गुना का उछाल आया है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी 2021-22 में 1 लाख 94 हजार 670 थी, जो अब बढ़कर 2 लाख 74 हजार रूपे तक पहुंच गई है। वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रगति 7.33 प्रतिशत रही। बीते चार साल में राज्य के मजूरी डायमंशनल सुधार आया है, वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत का मुकाबले, यह अब बढ़कर 6.92 प्रतिशत पर आ गया है। वहीं ब्रूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ष 2021-22 में च्याईट 718 (718) प्रतिशत था जो अब सुधर कर च्याईट 722 (722) प्रतिशत हो गया है। उद्योग को मिला बढ़ावा धामी सरकार के चार साल के कार्यकाल में राज्य के भीतर

एमएसएमडी इकाईयों की संख्या 59,798 से बढ़कर 79,394 तक पहुंच गई है, अकेले इस क्षेत्र में अब 4.56 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। बीते चार साल में लार्ज इंडस्ट्री 107 से बढ़कर 128 और स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,750 तक पहुंच गई है। साथ ही लेंबर फॉस पार्टिसिपेशन रेट भी 64.4% हो गया है। स्वास्थ्य सुचकांकों में सुधार राज्य में शिशु मृत्यु दर 2021-22 में 22 से घटकर 2024-25 में घटकर 20 हो गई है। इसी तरह मातृ मृत्यु दर भी 2021-22 में 103 से घटकर 2024-25 में 91 पर आ गई है।

साहसिक फैसलों से राष्ट्रीय फलक पर छाए मुख्यमंत्री धामी

चार साल बेमिसाल: 03 यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। इसी के साथ उत्तराखंड आजाद भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके फैसले ने इस देश में फैल को है। बड़े फैसले, बड़ा संदेश नकल विरोधी कानून से धार्मी प्रक्रिया में पारदर्शिता संमान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य रोपवे से समुचित के लिए विशेष कानून गैरगैर पंच और धर्मनिरपेक्ष कानून को सख्त बनाया है। पारदर्शी धार्मी प्रक्रिया के चलते बीते चार साल में प्रदेश में 30 हजार से अधिक युवाओं का सरकारी नौकरी मिल चुका है। गैरगैर पंच को बनाया सख्त धामी सरकार ने गैरगैर पंच में संशोधन करते हुए गोपाय, मानव तकनी, बाल अग्र, बंधुआ मजदूरी, नकल माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को इसके दायरे में ला दिया है। इसी तरह जबरन धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 10

एमएसएमडी इकाईयों की संख्या 59,798 से बढ़कर 79,394 तक पहुंच गई है, अकेले इस क्षेत्र में अब 4.56 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। बीते चार साल में लार्ज इंडस्ट्री 107 से बढ़कर 128 और स्टार्टअप की संख्या 702 से बढ़कर 1,750 तक पहुंच गई है। साथ ही लेंबर फॉस पार्टिसिपेशन रेट भी 64.4% हो गया है। स्वास्थ्य सुचकांकों में सुधार राज्य में शिशु मृत्यु दर 2021-22 में 22 से घटकर 2024-25 में घटकर 20 हो गई है। इसी तरह मातृ मृत्यु दर भी 2021-22 में 103 से घटकर 2024-25 में 91 पर आ गई है।

पीएम मोदी ने चार वर्ष के कार्यकाल पर राज्य सरकार को दी बधाई

शाह टाइम्स ब्यूरो देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखण्ड की मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के ऊर्जावान विकास के लिए मुख्यमंत्री ने नवल व राज्य विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि सधियों से आस्था, अध्यायन, साहस और समुद्र परंपराओं को भूमि रही है। यहां की विविध भाषाएं-बोलिएय, लोक परंपराएं और सरल जीवनशैली प्रदेश को विशिष्ट पहचान देती हैं। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी है, तब से उत्तराखंड 'विकसित भारत' के संकल्प के अड्डरूप लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चार धारा आंदोलन वेदर रोड परियोजना के तहत चारधारा बांध का सूर्योदय और सुभाष बनाने का कार्य तेजी से बढ़ रहा है, वहीं क्राफिकश-कर्मगणायार रवेक हासल के माध्यम से प्रदेश में रेल संयंत्र को मजबूती प्रदान जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने और शोलाकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का भी सराहा। उन्होंने कहा कि पहलुओं से न केवल प्रदेश की उन्नति बढ़ती है, बल्कि प्लापर राकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सराक



प्रधानमंत्री का संदेश-चार साल में विकास और सुशासन को नई पहचान बना उत्तराखंड

वना में भी मदद मिली है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार सुख, स्टार्टअप को बढ़ावा तथा डिजिटल और हरित विकास जैसे प्रयासों को सराहना किया। साथ ही, आदाव धार्मी की सुदृढ़ व्यवस्था और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने विकास सजया कि 'अमूम काल' में विश्वास बनाने का धार्मी के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर, समुद्र और सुदृढ़ उत्तराखंड के निर्माण की संस्थापिता अहम है। अंत में प्रधानमंत्री ने राज्य के नागरिकों को भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल करेगा।











# केदारनाथ यात्रा की तैयारी को लेकर प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा

**शाह टाइम्स संवाददाता**  
**हल्द्वानी।** आगामी केदारनाथ यात्रा 2026 को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद के प्रभारी मंत्री सीरधर बहुगुणा ने विद्या सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत आकलन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तब समयसीमा के भीतर और आसानी से पूरे किए जाएं।

बैठक में जिलाधिकारी विद्याल मिश्रा ने जानकारी दी कि 22 अर्थव्यय से प्रस्तावित यात्रा के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर बिम्बोदारीय तब कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा को सुचारु रूप से चलायित करने के लिए हर स्तर पर तैयारियों तैयारी से आगे बढ़ रही है।

परपत्रित विभाग द्वारा यात्रा मार्ग पर संभावित चोट-घटकों का पंजीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही पर्यटकों के विपत्ति-स्वस्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और निगरानी को व्यवस्था सुनिश्चित



**■ 22 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा, सभी विभागों को प्रभारी मंत्री सीरधर बहुगुणा ने विद्या सभागार में कार्य पूर्ण करने के निर्देश, सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रेफिक प्रबंधन पर विशेष फोकस प्रोटेड-खच्चरों का पंजीकरण व स्वास्थ्य परीक्षण शुरू, डॉ. जे.जे. जॉर्ज ने विशेष सुरक्षा कार्य जारी, सभी विभागों को समयबद्ध और समन्वित कार्य के निर्देश, यात्रियों की सुरक्षा-सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता**

सुरक्षित और सुगम बनाना है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के तहत यात्रा मार्ग पर पर्याप्त एंजुलेंट तैयार की जाएगी। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के साथ विभिन्न पड़ावों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। आवश्यक दवाओं और उपकरणों को उपलब्धता सुनिश्चित कर आपात स्थिति में त्वरित उपचार को व्यवस्था को जारी है। प्रभारी मंत्री सीरधर बहुगुणा ने स्पष्ट कहा कि केदारनाथ यात्रा आस्था, संस्कृति और प्रवेश की अव्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे, साथ ही पार्किंग, ट्रेफिक प्रबंधन, पर्यटन, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता और आपात प्रबंधन को व्यवस्थापूर्व तरीके से सुचारु रूप से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए और शिकायतों के निस्तारण के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित की

जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव मिल सके।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, केदारनाथ विभागाध्यक्ष आशा नौटियाल सहित जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

# केदारघाटी में नशे के खिलाफ महिलाओं का बड़ा अभियान

**हल्द्वानी।** जिले में नया मुक्त समाज के निर्माण को लेकर महिलाओं ने एक प्रभावशाली चरण चले हुए जनजागरण का मजबूत संदेश दिया। विद्युत्निगरण गांव की महिलाओं ने संगठित होकर विद्युत्निगरण से संबंधित एक लक्ष्य 12 किमी/घंटा की गति से चलने वाली महिलाओं का उदाहरण देकर नया चेहरा बनाया और पूरे जिले में नशे के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। एएलएम के अध्यक्ष ने बहने नशे को प्रचलन पर रोक लगाया और समाज को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक बनाया। महिलाओं ने रातों रात लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया और विशेष रूप से युवाओं से इस मुद्दे से रूठने की अपील की।

## कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर

पत्रांक: 3760/भूखनि/वि/0/अभ/भपी-0-वि/ता/2025-26 दिनांक: 23 मार्च, 2026

### भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, रूद्रपुर

दिनांक 17.03.2026 को विभागीय दल द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील काशीपुर क्षेत्रांतर्गत अथैव खान की रोकथाम हेतु किये गये मौका निरीक्षण में ग्राम दभौरा एहलमाली में अथैव रूप से हेरियों में भण्डारित पाये गये उपखनिज को नियमावली के प्राविधानानुसार खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जाना है। नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा समस्त बांछित अभिलेख दिनांक 28.03.2026 को सायं 5 बजे से पूर्व तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बांछित अभिलेख एवं नीलामी की शर्तों एवं प्रतिक्रियों की जानकारी हेतु किसी भी कार्यालय पर भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, रूद्रपुर के कक्ष सं 115 में अवलोकित/प्राप्त किये जा सकते हैं।

कुटे खान अधिकारी  
ऊधमसिंह नगर

## डीएम ने जनता दबाव कार्यक्रम में सजी जन समर्थन

**हल्द्वानी।** जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने जनता मिशन कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 33 जनसमस्या पत्र दर्ज किए गए जिनका अधिक से अधिक मौके पर ही निस्तारण किया गया शेष शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को अधिकारिता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर ग्राम पंचायत रिमाल गढ़ सहसलाना के पूर्व प्रधान अजय सिंह गणा द्वारा दबीय आवदा से विवादात्मक की क्षतिग्रस्त दीवार लानाने की मांग, ग्राम चांची लल्ली की मोहन तालाब द्वारा ग्राम अपने निजी खेत में दुर्गमकरण इत्यादि, विवासी ग्राम बरगाडी शीलवार द्वारा खेत की सड़कों की मरम्मत व बस सेवा लगाने आदि शिकायत से प्राप्त हुई जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को जनसमस्या की समस्याओं को प्रसूचना से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

## पुरोला ठेकदारों की मनमानी, सच दिखाने पर पत्रकार को धमकी

**शाह टाइम्स संवाददाता**  
**पुरोला।** जनपद के पुरोला क्षेत्र से एक नभरी समाना सामने आया है, जहां सरकारी विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं को उजागर करने वाले पत्रकारों को दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह घटना न केवल स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि जनता और पत्रकारिता पर भी सीधा प्रहार करता है।

**BRIDICUL (विज्ञापन)**  
 Ref No: 1988/BRIDICUL-23326 Date: 23/03/2026

**On behalf of Managing Director, BRIDICUL, sealed Item Rate Tenders with Post Qualification, are invited in two separate envelopes (Technical and Financial) simultaneously from Contractors Empanelled with BRIDICUL in Electrical work Category-III (upto 2 Crore) and as per the detailed specification, terms & Conditions given in the tender documents for following work:-**

S. No.	Name of work	Estimated Cost with GST & All Security/EMD Taxes (In Lac)	Bid Price (In Rs.)	Cost of Tender Form	Tender Document can be obtained/ submitted at
1	Electrification Renovation work at 1 Head Office of Tourism Department (JTDH) Dehradun under ADB	12.10	36000.00	Rs. 5000/- + 18% GST	Project Unit BRIDICUL Dehradun
2	Electrification Renovation work at 2 Head Office of Tourism Department (JTDH) Dehradun-2nd Call	3.90	12000.00	Rs. 5000/- + 18% GST	Project Unit BRIDICUL Dehradun

The tender documents can only be purchased from the office of the respective Project Manager between 10.00 am to 5.00 pm on all working days from 24.03.2026 to 06.04.2026. The cost of tender document amounting to Rs 5000+18% GST, will be paid while purchasing the tender documents, by cash or Demand Draft in the favour of Project Manager, BRIDICUL, Dehradun. The tenders should reach the office latest by 15:00 hours on 06.04.2026 and the technical bid shall be opened at 15:30 hours on the same day in presence of tenders who choose to be present.

Project Manager, BRIDICUL

## कार्यालय जिला पंचायत, उत्तरकाशी

पत्रांक 1790/निगम/2025-26 दिनांक 23.03.2026

**निविदा सूचना (Tender Notice)**  
 जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा यात्रा व्यवस्था मर में निगम हेतु उत्तरखण्ड अधिप्रापित नियमावली, 2025 के अध्याय 4 में विहित प्रावधान (प्रसर 4.4.2) के अनुरूप, जिला पंचायत में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकदारों से रसीमित निविदा पृच्छा (Limited Tender Enquiry) आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि (2%)	निविदा शुल्क + GST(18%)	कार्य अवधि	श्रेणी
----------	--------------	------------	-------------------------	-----------------	-------------------------	------------	--------

1	डुमटा में शौचालय निर्माण कार्य	नोंगांव	5.00	10000	500	1 माह	A
2	बनीगाड में शौचालय निर्माण कार्य	नोंगांव	3.00	6000	500	1 माह	AB
3	कुधनीर में शौचालय निर्माण कार्य	नोंगांव	3.00	6000	500	1 माह	AB
4	पालीगाड में शौचालय निर्माण कार्य	नोंगांव	3.00	6000	500	1 माह	AB
5	खरसाली में शौचालय निर्माण कार्य	नोंगांव	5.00	10000	500	1 माह	A
6	स्थानचट्टी में शौचालय निर्माण	नोंगांव	3.00	6000	500	1 माह	AB
7	जानकीचट्टी में चोड़ा पड़ाव का नव निर्माण कार्य	नोंगांव	10.00	20000	1000	1 माह	A
8	यमुनोत्री यात्रा हेतु जानकीचट्टी से यमुनोत्री तक शौचालय व चरियों एवं लीट पर मरम्मत कार्य	नोंगांव	12.00	24000	1000	1 माह	A
9	चढ़ेती में शौचालय निर्माण कार्य	भटवाडी	3.00	6000	500	1 माह	AB
10	हीना पार्किंग के पास शौचालय निर्माण कार्य	भटवाडी	3.00	6000	500	1 माह	AB

**निविदा समय-सारणी-**

- निविदा प्रपत्र विक्रय प्रारंभ तिथि: (दिनांक 25/03/26)
- निविदा प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि: (दिनांक 04.04.26) (सायं 5:00 बजे तक)
- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि: (दिनांक 05.04.26) (अपराह्न 2:00 बजे तक)
- निविदा खोलने की तिथि: (दिनांक 05/04/26) (अपराह्न 2:30 बजे)

**!! निविदा की शर्तें एवं नियम (Terms & Condition) !!**

- पंजीकरण एवं अर्हता: निविदा में केवल वही ठेकदार भाग ले सकते हैं जिनका जिला पंचायत में वर्ष 2025-26 हेतु विधिवत पंजीकरण वैध हो। निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- जी.एच.डी. 020 अर्हता (अनिवार्य): उत्तरखण्ड शासन, वित्त अनुभाग के पत्र संख्या 2238/17 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार पंजीकृत, निविदा के साथ जी.एच.डी. अर्हता प्रमाण पत्र (GST Non Dues Certificate) तथा समस्त देय विवरण (Return) जमा होने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा शर-प्रतिक्रियाशील (Non & Responsive) मानी जाएगी।
- धरोहर राशि (EMD): प्रत्येक निविदादाता द्वारा कार्य हेतु (अनिवार्यतः) उक्तनुसार निर्धारित धरोहर राशि (2%) अथवा अनुभव अधिकारी, जिला पंचायत उत्तरकाशी को नाम बन्धक एफ. डी. आर. (FDR), सी.डी.आर. (CDR) या बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करनी होगी।
- निविदा प्रतिक्रिया: अधोहस्ताक्षरी/अध्यक्ष जिला पंचायत को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह कोई कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अधिप्रापित निविदावली 2025 के प्रसर नियम 2.2.15 के अधीन निरस्त कर सकते हैं।
- अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्ययत्र के नोटिस बोर्ड में देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, उत्तरकाशी

## कार्यालय सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, उत्तरकाशी

संख्या 612/ल.सि./निविदा.स.अ.उ./2025-26 दिनांक: 23, मार्च, 2026

**अल्पकालीन निविदा सूचना**  
 महाप्रतिपद राज्यपाल महोदय, उत्तरखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय स्वीकृत योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु लघु सिंचाई विभाग, में पंजीकृत ठेकदारों से मुहरबन्द निविदा दिनांक 07.04.2026 के अपराह्न 2:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा के साथ बांछित धरोहर धराराशि राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र मान्यता प्राप्त बैंक के द्वारा प्रपत्र, एक 0.50+0.50 अथवा डाकघर, बचत पत्राधिकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के पदनाम से अर्हता, लाना आवश्यक अतिरिक्त निविदा प्रपत्र के साथ रु 100.00 के नान-ज्यूडिशियल स्ट्याम्प पेपर पर रु 1.00 का रसीद टिकट लगाकर वेबदात की सभी शर्तों के साथ ठेकदार द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड कार्यालय उत्तरकाशी से दिनांक 06.04.2026 तक कार्यालयबन्ध में निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं तथा दिनांक 07.04.2026 को अपराह्न 2:00 बजे तक लघु सिंचाई उपखण्ड कार्यालय उत्तरकाशी में जमा कराया जायेगा, जो कि उन्ही दिन सायं 2:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं से समक्ष अधोहस्ताक्षरी एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	विकास खण्ड	3% धरोहर धराराशि	निविदा की वैधता	कार्य प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	श्रेणी
1	ग्राम बनावडी में बेंचारा तोक में गूल मरम्मत कार्य	बनावडी	चिन्वालीसौड	12000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
2	ग्राम तराकट के खदारा तोक से हदल्ली तोक तक गूल मरम्मत	तराकट	चिन्वालीसौड	15000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
3	ग्राम भुयाय शिवांगी नामे तोक में गूल मरम्मत	भुयाय	चिन्वालीसौड	12000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
4	ग्राम धराली में चोलमी नामे तोक में अरविन्द नेगी आदि के बगीचों की सुरक्षा दीवार	धराली	भटवाडी	15000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
5	ग्राम बागों के इकराली तोक में परम सिंह आदि के बगीचों की सुरक्षा दीवार	बागों	भटवाडी	15000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
6	ज्ञानसू बाई नो-11 के प्रकाशनगर में रोपना देवी आदि के खेतों की रास्ते की सुरक्षा दीवार	ज्ञानसू	भटवाडी	4000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
7	गुफियाय बाई नो-02 में अनिल आदि के खेतों की रास्ते की सुरक्षा कार्य	गुफियाय	भटवाडी	12000.00	45 दिन	500+GST	03 माह
8	ग्राम सिंगोट के विलयनगरा के खेत में सुरक्षा कार्य	सिंगोट	डुण्डा	12000.00	45 दिन	500+GST	03 माह

**निविदा की शर्तें:-**

- निविदा खोलने की तिथि 07.04.2026 को प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक, कार्य करने हेतु इच्छुक ठेकदार के साथ प्रोविडेंट मॉर्टिज का जमापत्र।
- निविदा केवल विभाग में पंजीकृत वैध ठेकदारों को ही देनी जायेगी।
- विना शौल्ड लिफाफे के प्राप्त निविदा प्रपत्रों व सशर्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदा हेतु मनुअल 69/70 के समस्त प्राविधान लागू होंगे।
- निगम कार्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दिनांक 06.04.2026 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- निविदा के साथ धरोहर धराराशि केवल राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं राष्ट्रीय बैंक को एफ.डी.0+0.50 के रूप में जो जिला उत्तरकाशी के किसी भी डाकघर से बनाई गई हो एवं अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी के पदनाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य है।
- निविदा दरों की वैधता के लिए निविदा के साथ 100 रु का नान-ज्यूडिशियल स्ट्याम्प पेपर पर 1.00 रु का रसेन्ट टिकट पर हस्ताक्षर सहित सांभाल पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- सफल निविदादाता को सूचना मिलने पर एक सप्ताह के अन्दर NSC/KVP/National Bank को FDR/ बैंक गारंटी उत्तरखण्ड अधिप्रापित (प्रोबुसमेंट) नियमावली 2008 के अनुसार पांच प्रतिशत परफॉरमेंस गारंटी की धराराशि (धरोहर धराराशि सहित) अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बन्धक रखने हुए उपस्थित होना होगा अन्यथा जमा धरोहर धराराशि जब्त कर ली जायेगी।
- निविदा हेतु दी गई 5 प्रतिशत से अधिक / कम दरों पर शासनादेश संख्या 6447/111 (2) / 11-20 (सं.)/11 दिनांक 02.01.2013 के अनुसार अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी ली जायेगी। अतिरिक्त परफॉरमेंस गारंटी जमा न करने पर धरोहर धराराशि जब्त कर ली जायेगी।
- सशर्त एवं अपूर्ण निविदा मान्य नहीं होगी।
- प्रतिशत दरें ही मान्य होंगी।
- कक्ष द्वारा निविदा मांगने पर निविदा मूल्य के अतिरिक्त डाक व्यय वहन करना होगा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- 13 Schedule "B" में दी गई मात्रा बट बट सकती है।
- 15 जेसे ठेकदार जो पूर्व से विभाग में कार्य कर रहे हैं और वे अनुभव्य को शर्तानुसार समयावधि तक पूर्ण करने में असमर्थ रहे हो अथवा कार्य की प्रगतिबता स्तरीय न रही है, उनको निविदा पर विचार्य हस्तगुस्तिका भाग-VI के प्रस्तर 364 को ध्यान में रखते हुए ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- श्रेणी के मूल्य के अनुसार ही ठेकदार को निविदा विक्रय को जायेगी।
- 17 ठेकदार के जो बंधक से नियमानुसार आयक / G.S.T / रॉयल्टी / लेबर सेस को कटौती की जायेगी।
- 18 शोड्यूल-बी में दर्शाई गयी सभी दरें सामग्री सहित है। विभाग द्वारा कोई सामग्री निर्गत नहीं की जायेगी।

(सतीश कुमार शर्मा),  
सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उपखण्ड, उत्तरकाशी



## जंग बंद होगी!

ईरान-इस्राइल/अमेरिका युद्ध के 24वें दिन एक अच्छी खबर आई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पांच दिन के लिए अपनी ओर से ईरान पर किसी तरह के हमले पर रोक की बात कही। विशेषकर ईरान के पॉवर प्लॉट को लेकर। जैसाकि हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज खाड़ी को बंद करने को लेकर ईरान को 48 घंटे का समय दिया था, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने 48 घंटे के भीतर होर्मुज को नहीं खोला, तो वह उसके पॉवर प्लॉट पर हमला कर देंगे, जिसके चलते ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। हालांकि बदले में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की भाषा के जवाब में चेतावनी दी थी कि अगर इस तरह की कोई कोशिश हुई तो ईरान भी बदले की कार्रवाई करेगा और यूईई सहित तमाम अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोलेगा। जब ऐसा लग रहा था कि यह युद्ध और भड़कने की ओर जा रहा है, तभी ट्रम्प ने 48 घंटे की समय सीमा खत्म होने से पूर्व ही बड़े ही नाटकीय अंदाज में पांच दिन के लिए एक तरह से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। साथ ही यह भी जानकारी दी कि ईरान के साथ उनके प्रतिनिधि विटर्काफ और कुशनर के बीच ईरान से बातचीत हुई है। फॉक्स बिजनेस ने दावा किया है कि यह बातचीत रविवार की रात हुई और इसमें तुर्की, पाकिस्तान और इंडिजिट के अधिकारी शामिल थे। फॉक्स बिजनेस के अनुसार इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल थे। हालांकि ईरान ने ऐसी किसी बातचीत से इन्कार किया है, क्योंकि ईरान का मानना रहा है कि जब भी बातचीत होती है, तभी अमेरिका धोखा देता है। अब पढ़ें कि पीछे चली बातचीत में कितनी सच्चाई है, यह तो आगे पता चलेगा कि इस पर कितना अमल जमीन पर दिखाई देता है, लेकिन एक बात साफ है कि ईरान ने जिस तरह विश्व की दो बड़ी परमाणु शक्तियों के साथ टकराव में बड़ी टक्कर दी है, उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। जहां तक बात ट्रम्प की है, वह अपनी बातों को बदलने में माहिर माने जाते हैं। इसलिए उनकी बातों को कोई अब गंभीरता से भी नहीं लेता। अभी भी वह यही कह रहे हैं कि ईरान उनसे समझौता करना चाहता है और यह युद्ध जीत चुके हैं और ईरान की शक्ति को बुरी तरह कुचल चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात एक अलग ही कहानी बयान करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कहीं भी यह नहीं लगता कि ईरान जरा भी पीछे हटने के लिए तैयार है। होर्मुज को लेकर उसने सभी को चेतावनी दी है और कहा है कि जो ईरान के मित्र देश हैं, उनके लिए यह पूरी तरह खुला है और यदि यह बंद है, तो उन देशों के लिए है, जो इस्राइल व अमेरिका के हितों की रक्षा करने में लगे हैं। जहां तक बात भारत की है, भारत भी इस युद्ध से बुरी तरह प्रभावित है और उसका मानना रहा है कि यह युद्ध शीघ्र बंद हो, सोमवार को प्रधानमंत्री ने संसद में दिए अपने संबोधन में अपने इसी स्टैंड को दोहराया है।

### नौ वर्षों में राज्य ने की अभूतपूर्व प्रगति

आध्यात्मिक प्रेरणा और जनसहभागिता के बल पर उत्तर प्रदेश ने बीते नौ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है, प्रदेश आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है व प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है, सरकारी योजनाओं के प्रभाव से महिलाएं अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, 2017 में प्रदेश को युवा राजगार के लिए पलायन करने को मजबूर था, जबकि आज उत्तर प्रदेश रोजगार और निवेश का केंद्र बनकर उभरा है, अब गरीब और श्रमिक वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जिसके लिए अटल आवासीय विद्यालयों जैसी पहलों की गई हैं।

-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश



पश्चिम बंगाल की सत्ता का रण एक बार फिर सज चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जहां की राजनीति हमेशा से ही प्रतिबद्धता और प्रतिरोध की प्रयोगशाला रही है, लेकिन इस बार का यह महामुकाबला केवल यह तय नहीं करेगा कि कोलकाता के ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग में अगला मुख्यमंत्री कौन बैठेगा, बल्कि यह भारतीय चुनाव आयोग की उस वैश्विक साख की भी सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है, जिसने 2021 के चुनाव और उसके बाद हुई भीषण हिंसा के दग को धोने और हिंसा मुक्त बंगाल का संकल्प लिया है। मसलान इस बार का चुनाव न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिहाज से एक बड़ी चुनौती वाला चुनाव है। आयोग ने इस बार अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए पिछले 8 चरणों के लंबे कार्यक्रम को घटाकर मात्र दो चरणों में समेटने का साहसिक फैसला लिया है, जो अपने आप में एक बड़ा दावें माना जा रहा है। हालांकि इसका असली परिणाम 23 और 29 अप्रैल को होने वाले दोनों चरणों के मतदान की शांति और सुरक्षा से तय होगा?

पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में हिंसा एक ऐसा शब्द रहा है जिसने लोकतांत्रिक उत्सव को कई बार फोका दिया है। 2021 के चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा के कड़वे अनुभवों को देखते हुए, इस बार चुनाव आयोग का पूरा जोर हिंसा मुक्त मतदान पर है, जिसके लिए पिछले सप्ताह कोलकाता का तीन दिवसीय दौरा करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई (एम), कांग्रेस और अन्य दलों से स्वरु होकर स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने हिंसा, धमकाने की कोशिशों और चुनाव कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का ऐलान किया है। मुख्य आयुक्त ने जोर देकर कहा कि आयोग पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब सवाल है कि क्या यह विधानसभा चुनाव राज्य के चुनावी इतिहास में हिंसा-मुक्त होने का नया कौतिलमान स्थापित कर पाएगा? हालांकि यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आयोग की सक्रियता ने उन मतदाताओं में भरोसा जरूर

# पश्चिम बंगाल चुनाव : सत्ता की जंग से बड़ी चुनाव आयोग की साख की अग्नि परीक्षा



जगाया है, जो लंबे समय से शांतिपूर्ण मतदान की बात जोह रहे हैं। एक मायने में यह चुनाव न केवल बंगाल का भविष्य तय करेगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था को भी पुनः स्थापित करेगा। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार इस बार पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को उत्तर बंगाल और जंगलम, हल के इलाके की 152 सीटों और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को दक्षिण बंगाल और कोलकाता के आसपास के इलाके की 142 सीटों पर मतदान होगा है। जबकि चुनाव के नतीजे चार मई को आएंगे।

### बेहद दिलचस्प मुकाबले के आसार

बंगाल की जमीन पर राजनीतिक बिसात भी दिलचस्प है, जहां चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी टीएमसी और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच आर-पार का है। वहीं पिछले चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद, वाम मोर्चा और कांग्रेस वाला गठबंधन इस बार श्रमसंगिकता बचाने की जंग लड़ रहा है। टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने चौथी बार सत्ता बरकरार रखने की बड़ी चुनौती है, जिसमें टीएमसी को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और एंटी-इनकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) से लड़ना है। सत्तापक्ष के लिए हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उपजे विवाद भी थी किसी चुनौती से कम नहीं होगा, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। आयोग के एसआईआर और केंद्रीय फंड में हो रही कटौती को लेकर फैली बेचैनी ने बंगाल में खासतौर से टीएमसी के लिए राजनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं।

वहीं 2021 में 77 सीटों जीतने वाली भाजपा इस बार सत्ता परिवर्तन की पुरजोर कोशिश में जुटी है। पार्टी व्यापक चुनावी रणनीति के साथ घुसपैठ और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को आधार बना रही है, लेकिन उसे अभी भी स्थानीय स्तर पर एक सर्वमान्य मजबूत नेतृत्व और सांगठनिक एकजुटता की तलाश है। भले ही सीटों के मामले में टीएमसी आगे दिख रही हो, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में फासला बहुत कम रह गया है, जिसमें यह आंकड़ा बताता है कि बंगाल का मुकाबला बेहद करीबी होने वाला है। हालांकि क्या जमीन पर यह आंकड़े हकीकत में बदलेंगे या 4 मई के नतीजे कुछ और ही कहानी कहेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

### सुरक्षा आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता

पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में हिंसा एक ऐसा शब्द रहा है जिसने लोकतांत्रिक उत्सव को कई बार फोका दिया है। 2021 के चुनाव और उसके बाद हुई हिंसा के कड़वे अनुभवों को देखते हुए इस बार आयोग का पूरा जोर हिंसा मुक्त मतदान पर है। इसी रणनीति के तहत चुनाव आयोग चुनावी घोषणा से पहले ही केंद्रीय बलों 480 कंपनियां राज्य में भेज चुका है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय बलों का उपयोग केवल मतदान के दिन ही नहीं, बल्कि मतदाताओं में विश्वास पैदा करने के लिए बलों द्वारा एरिया डोमिनैन्स और गश्त में पहले से कर रहा है। वहीं दागी अधिकारियों को लेकर भी चुनाव आयोग पूरी तरह से मुत्सद्द है यानी आयोग इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए आयोग ने उन पुलिस अधिकारियों की सूची मांगी है जिन पर पिछले चुनावों में हिंसा के बढ़ावा देने या लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे। ऐसे दागी अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के लिए आयोग ने उन्हें हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं चुनाव आयोग इस बार शफर्जी मतदान की गुंजाइश खत्म करने की दिशा में मतदान केंद्रों के बाहर चेहरा सत्यापन के लिए विशेष काउंटर बनाने पर विचार कर रहा है, जहां बुर्का या घूंघट वाले मतदाताओं की पहचान



ओ.पी. पाल

महिला कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।

### बंगाल के चुनावी एक्स फैक्टर

राजनीतिक जानकारों की माने तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं अक्बर साइलेंट वोटर होती हैं। र्संद, शिखरीर जैसी घटनाओं और श्लक्ष्मी भंडारर जैसी योजनाओं के बीच उनका झुकाव ही सत्ता की चाबी तय करेगा। राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती घोटाले युवाओं के बीच एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। बंगाल में बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने नए अवसर पैदा किए हैं। कभी बनर्जी को संदेह की नजर से देखने वाले शहरी बंगाली भद्रलोक मतदाता अब एसआईआर के दखल को लेकर अपनी नाराजगी सजाकर रहे हैं। वहीं, मत्तुआ और राजबंशी जैसे समुदाय जिनके समर्थन ने भाजपा को बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में खड़ा करने में मदद की थी, अब उनमें भी बेचैनी के संकेत दिख रहे हैं। उत्तर बंगाल में भाजपा की पकड़ मजबूत रही है, जबकि दक्षिण बंगाल टीएमसी का किला है। इस बार दोनों दल एक-दूसरे के गढ़ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव महज आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों मतदाताओं की उम्मीदों का परीक्षण है, जो दशकों से शांतिपूर्ण मतदान का सपना देख रहे हैं। यदि चुनाव आयोग हिंसा मुक्त मतदान कराने में सफल रहता है, तो यह भारतीय चुनाव प्रबंधन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। 4 मई के नतीजे यह बताएंगे कि बंगाल ने दीदी की निरंतरता को चुनाव पर परिवर्तन के कैसरिया संकल्प को पर भरोसा जताया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये लेखक के निजी विचार हैं)

# जयपुर की घटना ने पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल

एक तरफ होली और दीपावली जैसे त्योहार हिन्दुओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तो दूसरी तरफ ईद-उल-फितर जैसा त्योहार मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण होता है। विविध संस्कृति वाले इस देश में हमें एक-दूसरे के त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। एक-दूसरे के धर्मों तथा त्योहारों का सम्मान करके ही हम इस देश की साझा संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह ध्यान भी रखना होगा कि कोई भी त्योहार धार्मिक कट्टरता का प्रतीक न बने।



रोहित कौशिक

दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली पुलिस की वजह से दिल्ली के उत्तमनगर में ईद शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई। उत्तमनगर के मुद्दे को लेकर ईद से पहले कई तरह की अफवाहें फैली थीं। कुछ हिन्दू संगठनों द्वारा लगातार यह धमकी भी दी जा रही थी कि उत्तमनगर में ईद पर खून की होली खेली जाएगी। कुछ संगठनों ने यह धमकी भी दी थी कि इस बार हमारे घरों में होली नहीं मनी तो हम ईद भी नहीं मने देंगे लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से उत्तमनगर में ईद पर शांति रही। उत्तमनगर में भारी पुलिस बल तैनात था। इसके बावजूद कई संगठन के लोग उत्तमनगर पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। तरुण के परिवार ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई और कहा कि हमारा एक युवा इस दुनिया से चला गया लेकिन हम नहीं चाहते किसी का बेटा इस दुनिया से चला जाए। दूसरी तरफ ईद के दिन मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद जरूर बवाल हुआ। फरसा वाले बाबा की मौत के बाद भड़की हिंसा और उपद्रव के

मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। हिन्दू संगठनों ने आरोप लगाया कि गोरक्षक फरसा वाले बाबा की कुचल कर हत्या की गई है लेकिन पुलिस का कहना है कि मौत सड़क हादसे में हुई है। दरअसल ईद से पहले और ईद पर उत्तमनगर के साथ ही देश के कई हिस्सों से अफवाह फैलने की बखर्त आई। ईद पर उत्तमनगर और देश के विभिन्न हिस्सों में तनाव की आशंका के बीच एक अच्छी खबर आई। जयपुर में ईद के अवसर पर हिन्दू समुदाय के लोगों ने मुख्य ईदगाह में नमाज अदा कर रहे मुस्लिमों पर फूल बरसाए। यह सराहनीय पहल हिन्दू-मुस्लिम एकता समिति के तत्वावधान में की गई। इस पहल का उद्देश्य भाईचारे और एकता का संदेश देना था। इस अवसर पर हिन्दू-मुस्लिम एकता समिति के सदस्य राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि ईद का त्योहार शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यह भावना राजस्थान सहित पूरे भारत में बरकरार रहनी चाहिए। कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं लेकिन यह गलत है। उन्होंने कहा कि राम के बिना रमजान नहीं है और ईद के बिना दीवाली नहीं है। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। जयपुर की यह पहल दिखाती है कि यही असली हिन्दुस्तान है। एक ऐसा हिन्दुस्तान जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता है। फिर कौन हैं वे लोग जो हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच दूर डालना चाहते हैं? कौन हैं वे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत परोसते हैं? कौन हैं वे लोग जो बार-बार यह कहते हैं कि मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे?

ऐसे लोग आपको और हमारे बीच ही मौजूद हैं। जी हां, वे लोग बाहरी लोग नहीं हैं। वे लोग अपने ही लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसते रहते हैं। ऐसे लोग हर मुसलमान को शक की नजर से देखने के आदी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग ए नहीं समझ पाते कि भारत का ज्यादातर ईधन खाड़ी या अरब देशों से ही आता है। यानी जहां से हमारे देश का ज्यादातर ईधन आता है, वे मुस्लिम देश हैं। हाल ही में जब गैस एजेंसियों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगीं और लोगों को कई-कई दिन तक सिलेंडर नहीं मिला तो सबसे साथ मुसलमानों को गाली देने वाले तथाकथित हिन्दू नेताओं की हालत भी खराब हो गई। तब किसी हिन्दू नेता ने नहीं कहा कि हम मुस्लिम देशों से आने वाले ईधन को नहीं लेंगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि हिन्दुओं को बिना मुसलमानों का काम नहीं चल सकता है और मुसलमानों के बिना हिन्दुओं का काम नहीं चल सकता है। इसलिए एक-दूसरे के लिए नफरत पैदा करके हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे बल्कि अपना ही नुकसान करेंगे। हमारे देश पर कई सालों तक मुगलों ने राज किया फिर अंग्रेजों ने कई सालों तक राज किया लेकिन सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर आज सनातन धर्म को खतरा पैदा कैसे हो गया? स्पष्ट है कि सनातन धर्म पर कोई खतरा नहीं है बल्कि खतरा दिखाकर अपना उद्भूत सीधा किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसी जा रही है।

# टीबी उन्मूलन की दिशा में वैश्विक प्रयास और भारत की रणनीति

टीबी (ट्यूबरकुल बेसिलाइड), जिसे क्षय रोग, तपेदिक अथवा राजरोग के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी संक्रामक बीमारी है, जो माइको ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। जैसे तो टीबी बाल और नाखूनों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है लेकिन इसका ज्यादातर असर फेफड़ों पर ही होता है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खाने-पीने के दौरान मुंह व नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के जरिए कोई स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। ड्रॉपलेट्स के जरिए फैलने वाले बैक्टीरिया कई घंटों तक हवा में रह सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक केवल फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक होती है, शरीर के अन्य हिस्सों में यह संक्रामक नहीं होती। दरअसल फेफड़ों के अलावा टीबी मुंह, लिवर, गले, दिमाग, किडनी, रीढ़ तथा यूरस में भी हो सकती है किन्तु ऐसी टीबी मरीज से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। इस बीमारी को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शरीर के जिस हिस्से में होती है, धीरे-धीरे उस हिस्से को बेकार करना शुरू कर देती है।

कुछ दशक पूर्व टीबी को एक लाइलाज बीमारी माना जाता था लेकिन अब सही समय पर इसका समुचित इलाज करके आने से इसका पूरी तरह निदान संभव है और इलाज शुरू करने के बाद उसमें लापरवाही मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीबी अभी भी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक जानलेवा बीमारियों में से एक है

और दुनियाभर में प्रतिदिन करीब 4 हजार लोग इससे जान गंवाते हैं। प्रतिदिन करीब 30 हजार लोग इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। हालांकि आज टीबी का इलाज उपलब्ध होने पर ऐसे लोगों का सफल इलाज संभव है लेकिन जागरूकता के अभाव में हर साल लाखों लोग अब भी टीबी होने पर मौत के मुंह में समा जाते हैं। इस वैश्विक महामारी के जानलेवा परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा इसे जड़ से खत्म करने के प्रयास तेज करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और डब्ल्यूएचओ के तत्वाधान में विश्वभर में टीबी से संबंधित कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 24 मार्च 1882 को एक जर्मन चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. रॉबर्ट कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया की पहचान करने की पुष्टि की थी, जिसके फलस्वरूप टीबी के निदान और इलाज में दुनियाभर में वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली। रॉबर्ट कोच की इस महत्वपूर्ण खोज के पूरे 100 वर्ष बाद 'इंटरनेशनल यूनियन अगेस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज' द्वारा 24 मार्च के दिन को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की गई। हालांकि डब्ल्यूएचओ की विश्व स्वास्थ्य सभा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दशक से भी ज्यादा समय बाद आधिकारिक तौर पर इसे एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में चिह्नित किया गया। डब्ल्यूएचओ ने 1995 में नीदरलैंड के डेन हैग में इसके लिए रॉयल नीदरलैंड ट्यूबरकुलोसिस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया और कुछ और संगठनों के साथ आने



पर विश्व टीबी दिवस को सफल बनाने के लिए 1997 में डब्ल्यूएचओ ने बर्लिन में एक समाचार सम्मेलन आयोजित किया, जहां डॉट्स को उस दशक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सफलता बताया गया। तभी डब्ल्यूएचओ द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला विश्व टीबी दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है और विश्व क्षय रोग दिवस 2026 का आधिकारिक विषय है 'हो! हम टीबी को खत्म कर सकते हैं' देशों के नेतृत्व में, लोगों की शक्ति से। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित इस विषय में राष्ट्रीय नेतृत्व, समुदाय-संचालित प्रयासों और टीबी महामारी से निपटने में प्रगति को तेज करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है, विशेष रूप से निवेश और नवाचार में वृद्धि के माध्यम से। टीबी का

खात्मा करने की रणनीति के तहत डब्ल्यूएचओ 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों को 95 फीसदी तक और टीबी के एम मामलों को 90 फीसदी तक कम करने पर काम कर रहा है। विश्व को टीबी मुक्त करने की डब्ल्यूएचओ की रणनीति के तहत टीबी रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्रों की स्थापना, सभी देशों द्वारा टीबी को लेकर सार्थक कदम उठाने और टीबी को खत्म करने वाली प्रणालियों पर कार्य करने की अनिवार्यता तथा टीबी को लेकर गहन अनुसंधान और नवाचार को शामिल करने जोर दिया जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक, वर्ष 2000 से टीबी को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों से अनुमानित 7 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई गई है। टीबी उन्मूलन की दिशा में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' की शुरुआत की जा चुकी है। हालांकि देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाकर कार्य करना निरसंदेह बड़ी पहल है लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि पोलियो उन्मूलन के प्रयासों की ही भांति टीबी उन्मूलन की दिशा में भी पूरी तैयारी के साथ कड़ी मेहनत की जाए ताकि इस अभियान को प्रगति न लगे। दरअसल आमतौर पर ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि टीबी के लिए आवश्यक अस्पतालों और कर्मियों



योगेश कुमार गोयल

का उपयोग दूसरे कार्यों में होता रहा है। टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है कि सरकारी मशीनरी को बेहद चुस्त-दुरुस्त बनाते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टीबी से मुक्ति प्राप्त के लिए निर्धारित संधानों का बेहतर उपयोग हो और टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत और सक्रिय बनाया जाए। समुचित इलाज के बावजूद टीबी के महामारी बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों में अभी भी इस बीमारी के प्रति जानकारी का अभाव है। देश में टीबी फैलने का प्रमुख कारण इस बीमारी के प्रति लोगों का सचेत न होना तथा शुरूआती दौर में इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेना ही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक टीबी किसी को भी हो सकती है लेकिन लोगों को इसके लक्षणों, बचने के उपायों तथा इलाज के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज टीबी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, 'डॉट्स' से हाथ मिलाकर टीबी जैसी जानलेवा बीमारी को हराया जा सकता है, बशर्त डॉक्टर के निर्देशानुसार इलाज में कोई लापरवाही न बरती जाए।

